दुधालिया में महिला सशक्तिकरण जनसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा

झालावाड़ जिले में पहली बार एक मंच पर नज़र आये वर्तमान व पूर्व मुख्यमंत्री

झालावाड़, 22 दिसंबर (निसं)। राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले के डग क्षेत्र की ग्राम पंचायत दुधालिया में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन एवं जनसभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल ने जनसभा में अरावली विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा कि केवल डीपी बदलने और ट्वीट करने से काम नहीं चलता, हमारी सरकार काम करके दिखाती है।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोमवार को झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत दुधालिया में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद दुष्यंत सिंह, प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में नौकरियों में भारी भ्रष्टाचार हुआ, जबकि उनकी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ।

मुख्यमंत्री ने अरावली विवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल डीपी बदलने और ट्वीट करने से काम नहीं चलता, हमारी सरकार काम करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है।

कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि दुधालिया एक पुण्य भूमि है। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज विकास की दौड़ में अग्रणी राज्यों में शामिल है।

सांसद दुष्यंत सिंह ने स्वागत उद्बोधन में मुंबई कॉरिडोर से जुड़ने वाली सड़कों, सिंचाई, पर्यटन, मेडिकल सुविधाओं और अभयारण्यों के विकास की मांग रखी। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

झालावाड़ जिले में आयोजित इस कार्यक्रम में पहली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक मंच पर नजर आए। दो वर्षों के कार्यकाल में यह पहला अवसर रहा जब दोनों नेताओं की संयुक्त उपस्थिति जिले में हुई, जिसे राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है।

वनरक्षक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करतारपुरा स्थित किराए के मकान पर पहली पारी के दो अभ्यर्थियों को लीक पेपर पढ़ाया था। दूसरी पारी के दो अभ्यर्थियों को लालसोट रोड पर पेपर पढ़ाया था, जिनमें से एक उसका साला सौरभ कुमार मीणा था।

एसओजी की जांच में पता चला कि जेडीए के लेखाकार अमन ने जबराराम के एक सहयोगी से लीक पेपर हासिल किया था। लीक पेपर पढ़ाने के बदले उसने चारों अभ्यर्थियों से 9.50 लाख रुपए लिए। अब एसओजी ने अमन जोरवाल और सौरभ कुमार मीणा को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या बंगाल में भाजपा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के भाजपा -विरोधी रुझान को समाप्त करने में सक्षम सिद्ध होंगे।

बिहार के विपरीत, भाजपा द्वारा पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर अधिक आक्रामक रणनीति अपनाने की संभावना है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य बाँग्लादेश से जुड़ा हुआ है। हाल ही में कोलकाता में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस बहस को उठाया था, जब उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों से खतरों के मद्देनजर हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। भागवत ने यह भी कहा था कि "भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र था" तथा यह चीज कोई अर्थ नहीं रखती कि संसद में इसे हिन्दू राष्ट्र घोषित करने का कानून पारित होता है या नहीं।

- **शायद भाजपा को भी इस नीति पर भरोसा कुछ कम है इसीलिए पार्टी जोर शोर से अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है, और भाजपा के नेता उग्र बयान दे रहे हैं।**
- **इससे एक बात साफ है कि बंगाल के चुनाव ना केवल ध्रुवीकरण की ओर, बल्कि बेहद संवेदनशील चुनावी माहौल की तरफ बढ़ते लग रहे हैं।**

ऐसी जोशपूर्ण बयानबाजी आने वाले हफ्तों में भी जारी रहने की संभावना है, क्योंकि भाजपा के नेताओं, जिसमें केन्द्रीय मंत्री भी शामिल हैं, के बड़ी संख्या में राज्य में आने की संभावना है। बंगाल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, या कहें कि, एक संवेदनशील चुनावी माहौल की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

ऐथनॉल ब्लैंडिंग में 20 प्रतिशत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसके बाद है ब्राज़ील, जिसकी हिस्सेदारी 33.2 बिलियन लीटर (28.1 प्रतिशत) है। भारत तीसरे स्थान पर है, और चीन (4.5 बिलियन लीटर), कैनडा (1.8 बिलियन लीटर), और थाईलैंड (1.4 बिलियन लीटर) से आगे है।

ईएसवाई 2025-26 के लिए तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी निविदाओं के अनुसार, भारत अब ऐथनॉल की सरप्लस आपूर्ति के साथ आगे बढ़ रहा है, जिससे और अधिक लाभ हासिल किया जा सकता है।

कुल मांग 1,350 करोड़ लीटर (जिसमें ईबीपी के लिए 1,050 करोड़ लीटर शामिल हैं) तथा आपूर्ति की पेशकश 1,775 करोड़ लीटर की है और स्थापित क्षमता 1,900 करोड़ लीटर है। यह सरप्लस विविध फीडस्टॉक आपूर्ति के कारण संभव हो पाया है, जो स्थिर और सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जैसे मक्का: 46 प्रतिशत, एफसीआई चावल: 22 प्रतिशत, गन्ने का रस: 16 प्रतिशत और अन्य: 16 प्रतिशत।

11 नवम्बर 2025 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, राज्य सभा सांसद पीवी वीत्तिल अब्दुल वहाब ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से पूछा कि क्या ऐथनॉल ब्लैंडेड पेट्रोल का वाहनों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। गडकरी ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि "आईओसीएल, एसआईएएम और एआरएआई द्वारा ई 20 पर किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि वाहनों ने प्रदर्शन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नताएँ नहीं दिखाईं दी हैं, और वाहनों के कल पुर्जों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।" बीएस6 चरण-2 के अनुरूप वाहन या जिन पर ई20 स्टिकर लगा है, वे 20 प्रतिशत तक के एथनॉल ब्लैंड को संभाल सकते हैं। समस्या पुरानी कारों के साथ है। हालांकि, यह माइलेज पर असर डाल सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन दक्षता में केवल 2-4 प्रतिशत की मामूली कमी होगी।

मोर का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल, पुलिस उप अधीक्षक राजीव राहर के सुपरविजन तथा ऋषभदेव थानाधिकारी हेमंत अहारी के नेतृत्व में एएसआई रमेश ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर लिया है।

'आईपीएस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने जिन मामलों की वजह से उनका प्रमोशन रोका है, उनकी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। जबकि कोर्ट ने पहले भी इन केसों की जांच समयबद्ध तरीके से पूरी करने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और जानबूझकर उनकी पदोन्नति रोक रखी है।

संसदीय समिति मनरेगा तथा वीबी-जी राम जी की समीक्षा करेगी

नयी दिल्ली, 22 दिसंबर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर संसद की स्थायी समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और विकसित भारत - गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी - जी राम जी) अधिनियम की समीक्षा करने के लिये 29 दिसंबर की प्रस्तावित बैठक में ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है।

- **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की स्थाई समिति ने 29 दिसम्बर की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को लिया गया है।**

इस नये कानून का मकसद ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी के लिये एक नया ढ ांचा देना है। इसे दो मुख्य आधारों पर विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ा है। पहला यह कि यह प्रभावी रूप से महात्मा गांधी के नाम पर चल रहे प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की जगह लेता है और उसे खत्म करता है। दूसरा यह कि नया अधिनियम पुरानी योजना से गांधी का नाम हटाता है, जिससे सरकार की मंशा पर विवाद खड़ा हो गया है।

ऐथनॉल ब्लैंडिंग की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजनीतिक अभियान बताया है, जिसे पेट्रोल लॉबी चला रही है, क्योंकि ईंधन आयात कम होने से उनके कारोबार पर असर पड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके बेटों की कंपनियों की हिस्सेदारी देश के कुल एथेनॉल उत्पादन में 0.5 प्रतिशत से भी कम है और एथेनॉल की कीमतें केन्द्रीय मंत्रिमंडल तय करता है, न कि उनका मंत्रालय। राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए गडकरी ने कहा कि यह नीति देश को ईंधन आयात पर लगभग 22 लाख करोड़ रुपये की बचत कराती है, प्रदूषण कम करती है और इसके कारण किसानों की आय में सालाना लगभग 45,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। व्यक्तिगत ईमानदारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके "दिमाग की कीमत 200 करोड़ रुपये प्रति महीना है" और उन्हें कमाई के लिए किसी तरह की धोखाधड़ी करने की जरूरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने ई20 नीति को लागू करने वाली नीति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि ऐसे नीतिगत फैसले सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

इसके साथ ही ए.आर.ए.आई. (ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया) और सियाम (सोसाइटी ऑफ इण्डियन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन) जैसी सरकारी संस्थाओं ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अगर कैलिब्रेटेड गाड़ियों में ई20 फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए तो इंजन परफॉर्मेंस पर इसका कोई खास नैगेटिव असर नहीं पड़ता है।

नीति के स्तर पर भारत ने 2025 में ही 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो पहले 2030 तक तय किया गया था।

'भारत हिंदू राष्ट्र है'

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संस्कृति का सम्मान करता है। जब तक हिंदुस्तान की धरती पर एक भी ऐसा व्यक्ति जीवित है जो अपने भारतीय पूर्वजों की महानता में विश्वास करता है और उसे सहेज कर रखता है, तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। यही संघ की विचारधारा है। उन्होंने आगे कहा, अगर संसद कभी संविधान में संशोधन कर उस शब्द को जोड़ने का फैसला करती है, तो चाहे जो हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उस शब्द की परवाह नहीं है, क्योंकि हम हिंदू हैं और हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। यही सच्चाई है। जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था हिंदुत्व की पहचान नहीं है।

बीएमसी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वाली महा विकास अघाड़ी का हिस्सा है, को स्वतंत्र रुप से सीटों में कोई हिस्सेदारी नहीं मिली है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908